Budget Analysis Rajasthan Centre
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

दिनांक : फरवरी 2, 2016

प्रेस विज्ञप्ति

खर्च के इंतजार में पड़ा है करोड़ो का बजट

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द (बार्क), जयपुर के द्वारा विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में आगामी राज्य बजट पर स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ दो दिवसीय (1 व 2 फरवरी)राज्य स्तरीय बजट पूर्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के 2016–17 के बजट के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर चर्चा करके मांग पत्र बनाकर सरकार को पेश करना था। इस कार्यशाला में राज्य के स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों के करीब 60 से अधिक प्रतिनिधी सम्मिलित हुये। इस कार्यशाला में प्रमुख रुप से शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, बाल एवं महिला विकास, दलित एवं आदिवासी, घुमंतु तथा अल्प संख्यक समुदायों, कृषि, ग्रामीण विकास तथा श्रम एवं रोजगार आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

कार्यशाला के पहले दिन–1 फरवरी को जन स्वास्थ्य अभियान की छाया पचोली ने राज्य में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जिसमें प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में ढांचागत सुविधाओं की कमी, दवाइओं की अनुपब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के सुधार आदि पर चर्चा कर सुझाव दिये गये। इसके बाद राज्य में शिक्षा की स्थिति पर आस्था संस्थान की अश्वती वरियर ने अपने विचाार रखे। जिसमें शिक्षा के निजीकरण, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, पेयजल एवं शौचालय का अभाव, स्कूलों का समानीकरण, राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद करना आदि मुद्दों पर चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत किये गये।

कार्यशाला के अगले सत्र में बच्चों एवं महिला तथा जेंडर बजट संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गयी जिसमें विविधा के ममता जेठली तथा आर.आई.एच.आर. के विजय गोयल ने विचार रखे। जिसमें आंगनवाड़ियों की स्थिति में सुधार एवं इनमें कार्यकर्ताओं की संख्या में बढोतरी, बाल सुधार ग्रह का जिला स्तर पर प्रबंध, मिड डे मिल बजट में बढोतरी आदि सुझाव आये। इसक अलावा घरेलू हिंसा से प्रताडित महिलाओं के लिये विशेष प्रबंध, महिला पुलिस अफसरों की संख्या में बढोतरी, कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास की व्यवस्था आदि के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये गये।

इसी प्रकार राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदर्भ में रोजी रोटी अधिकार संदर्भ केन्द्र के अशोक खंडेलवाल ने अपने विचार रखे। जिसमें दालों और तेल को खाद्य सुरक्षा में शामिल करने तथा पेंशन की रकम कम से कम 1500 किये जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यशाला के दलित, आदिवासी एवं घुमंतु समुदायों के मुद्दों पर चर्चा वाले सत्र में दलित अधिकार केन्द्र के सतीश कुमार, एवं दलित कार्यकर्ता– भंवर मेघवंशी आदि ने विचार रखे। जिन्होने राज्य में उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन एवं इस हेतु कानून निर्माण, उपायजाओं के बजट आवंटन एवं खर्च की मोनिटरिंग, उपयोजनाओं में महिलाओं हेतु जेंडर बजटिंग को लागू करने के संबंध में विचार प्रस्तुत किये। इसके अलावा घुमंतु समुदायों के लिये अलग से बजट में प्रावधान एवं इनकी

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org

संस्कृति को बचाने के लिये एक कला केन्द्र की स्थापना हेतु मांग रखी गयी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिये छात्रवृति एवं छात्रावासों की व्यवस्था एवं इनके लिये किये गये बजट आवंटन एवं खर्च की मोनिटरिंग की मांग रखी गयी।

कार्यशाला के दूसरे दिन–2 फरवरी को प्रथम सत्र में राज्य में कृषि, पशुपालन तथा पेयजल एवं सिंचाई के विषयों पर सी.ई.डी.एस. के निदेशक प्रो. एम. एस. राठोड़ तथा विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक पी.एस.बीर्थल ने अपने विचार रखे। जिसमें इन्होने मुख्यरुप से वर्षा जल संरक्षण, कृषि अनुसंधान को बढावा देने के लिये बजट वृद्वि आदि पर जोर दिया। प्रो. एम. एस. राठोड ने जल स्वावलंबन अभियान की सफलता के लिये लघु सिंचाई बांधों के सुदृढीकरण एवं रखरखाव के लिए बजट आंवटन पर ज़ोर दिया।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम रोजगार एंव मजदूरी पर चर्चा की गया। जिसमें सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के कमल टांक ने महानरेगा संबंधी मुद्दों पर विचार रखे तथा इसके बजट में बढोतरी के लिये सुझाव दिया। इसके अलावा राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रिय विकास बोर्ड एवं निर्माण मजदूर बोर्ड के क्रियावयन संबंधी मुद्दों पर ए.एम.आई.डी के नूर मोहम्मद, एस.एन.वी.एस के गोपाल राम वर्मा तथा अशोक खंडेलवाल ने अपने विचार रखे तथा इनके क्रियांवयन में सुधार हेतु सुझाव दिये।एक बड़ मुद्दा विभिन्न बोर्ड तथा योजनाओं की राशि का उपयोग नहीं हो पाना भी पाया गया। उदाहरण के लिए सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014–15 तक करीब 279 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि में से 132 करोड़ रूपये खर्च नहीं हो पाये। मेवात क्षेत्रिय विकास बोर्ड के अंतर्गत अगस्त 2015 तक कुल 113 करोड रूपये की राशि खर्च नहीं हो पाई। इनके अलावा निर्माण मजदूर बोर्ड के अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक कुल 600 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा हुई थी जिसे बोर्ड खर्च नहीं कर पा रहा है।

अंत में सभी प्रतिभागियों ने पूरी बजट प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु किये जाने वाले उपायों पर चर्चा कर सुझाव दिये। कार्यशाला के अंत में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र जयपुर के समन्वयक नेसार अहमद ने आगन्तुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया।

नेसार

नेसार अहमद
समन्वयक,
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर